अध्याय

08

सेवा: दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियाँ

सेवा क्षेत्र से घरेलू और वैश्विक स्तर, दोनों के विकास को बढ़ावा मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025 में, अब तक, सेवाओं से जीडीपी वृद्धि को मदद मिली है, जबकि वैश्विक माल व्यापार में गिरावट के कारण विनिर्माण प्रभावित हुआ है। भारत के बाह्य संतुलन को मजबूत करने में सेवा निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका और औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता 'सेवाकरण' भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को बढ़ाते हैं। लॉजिस्टिक्स सेवाओं ने कोविड महामारी से पहले की अपनी गति को पुनः प्राप्त कर लिया है और डिजिटलीकरण के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बना रही हैं। भारत व्यावसायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीकों को अपनाने के माध्यम से बदलते वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसी पहल इन परिवर्तनों को और अधिक समावेशी बना रही हैं। श्रम शक्ति को अपेक्षित कौशल से लैस करना तथा जमीनी स्तर पर शासन की सरल और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण करना, वाणिज्यिक सेवाओं की पूर्ण क्षमता को साकार करने तथा वैश्विक चुनौतियों के प्रति समुत्थानशीलता बनाने में सहायक होगी।

परिचय

8.1 सेवा मूल्य संवर्धन का योगदान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 62 प्रतिशत है।[1] पिछले दशक में चीन, थाईलैंड और भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए सेवाएँ विकास का माध्यम रही हैं। वर्तमान में, यूरो क्षेत्र मंदी से जूझ रहा है, लेकिन सेवा गतिविधि में सुधार के कारण वर्ष 2025 में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, कोविड महामारी से पहले की तुलना में उच्च नाममात्र वेतन वृद्धि ने सेवा मुद्रास्फीति को उच्च रखा है। इससे वैश्विक अवस्फीति का वर्तमान चक्र धीमा हो गया है।[2]

8.2 ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स दिसंबर 2024 में चार महीने के उच्चतम स्तर 53.8 पर पहुंच गया। यह लगातार तेईसवें महीने के विस्तार को दर्शाता है। नए ऑर्डर इनटेक और रोजगार में वृद्धि भी मजबूत हुई, जबकि व्यापार भावना में वृद्धि हुई है। तथापि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, अर्थात संरक्षणवाद, युद्ध और जलवायु संबंधी चुनौतियों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को

1 विश्व विकास संकेतक – विश्व बैंक

2 आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य, अक्तूबर 2024

महत्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है।[3] आपूर्ति श्रृंखलाओं में ये व्यवधान वैश्विक सेवा परिदृश्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।

चार्ट VIII.1: वर्ष 2023 में जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार सेवाओं का मूल्यवर्धन और दशकीय परिवर्तन

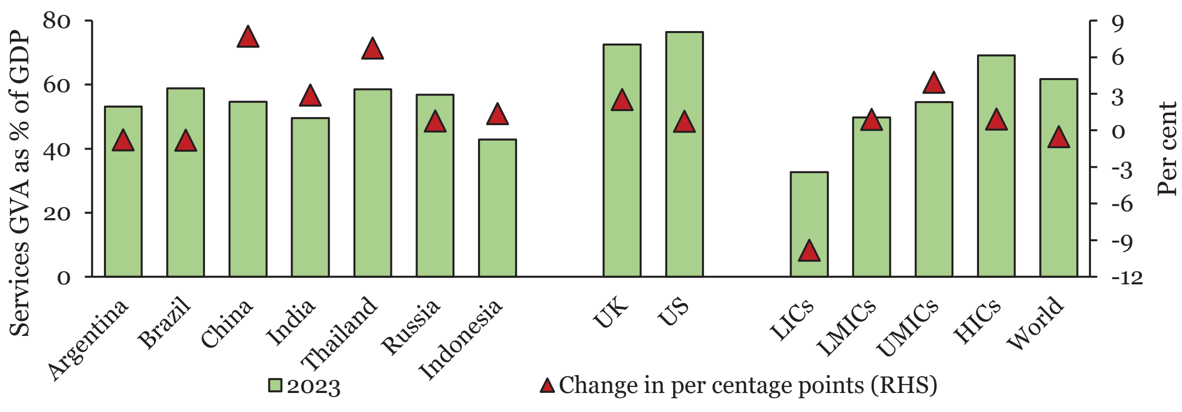

स्रोत: विश्व विकास संकेतक- विश्व बैंक

नोट: एलआईसी: निम्न आय वाले देश, एलएमआईसी: निम्न- मध्यम आय वाले देश, यूएमआईसी: उच्च- मध्यम आय वाले देश, एचआईसी: उच्च आय वाले देश

8.3 पिछले दो दशकों से वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इससे वैश्विक माल निर्यात में माल निर्यात की हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है। वर्ष 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका 13 प्रतिशत की प्रमुख हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेवा निर्यात में सबसे आगे था, उसके बाद 7.4 प्रतिशत के साथ यूनाइटेड किंगडम, 5.5 प्रतिशत के साथ जर्मनी और आयरलैंड, चीन और फ्रांस का स्थान है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत है। भारत वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर है, जो वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

चार्ट VIII.2: वैश्विक सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी

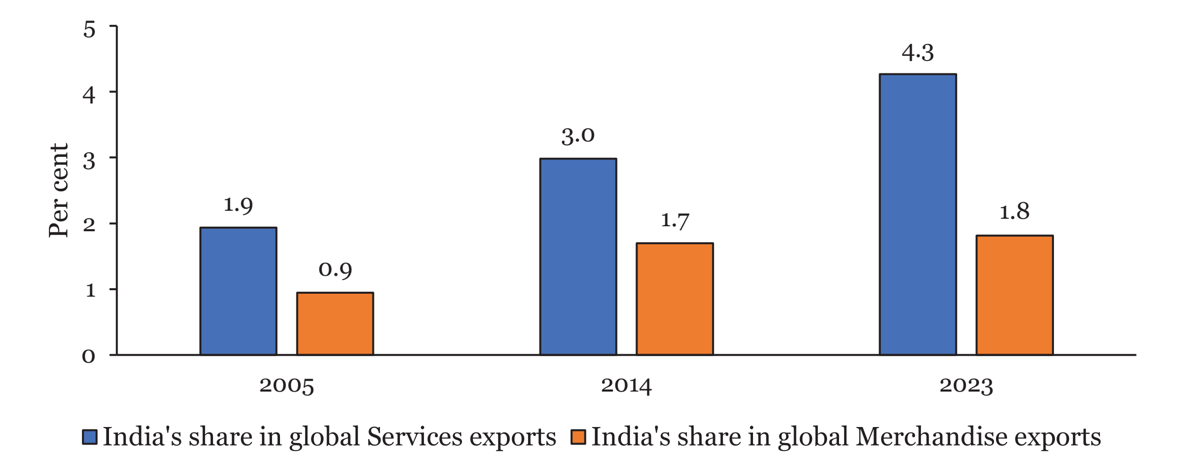

स्रोत: यूनाइटेड नेशनंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट

3 एसएंडपी ग्लोबल. (6 जनवरी, 2025) जेपी मॉर्गन ग्लोबल कम्पोजिट पीएमआई https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/f94e193ddf214de5bdfa79062611f26c से लिया गया है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

8.4 भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सबसे स्थिर योगदानकर्ता रहा है। वर्तमान मूल्यों पर कुल जीवीए में इसका योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55 प्रतिशत हो गया है। यह लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है। विनिर्माण के सेवाकरण, अर्थात, विनिर्माण उत्पादन में सेवाओं के उपयोग में वृद्धि और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्धन के माध्यम से सेवाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करती हैं।[4]

चार्ट VIII.3: सेवा जीवीए में वृद्धि

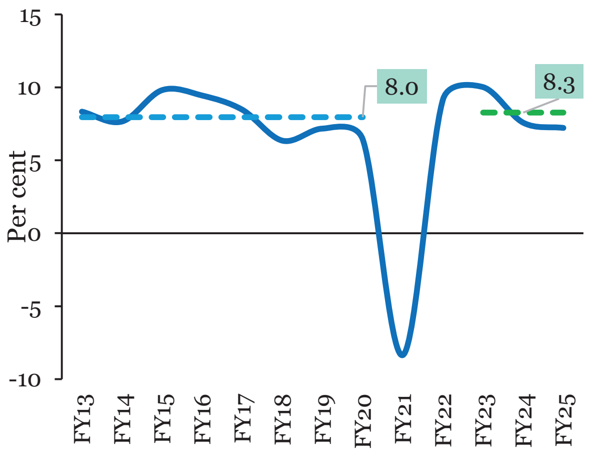

चार्ट VIII.4: जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी

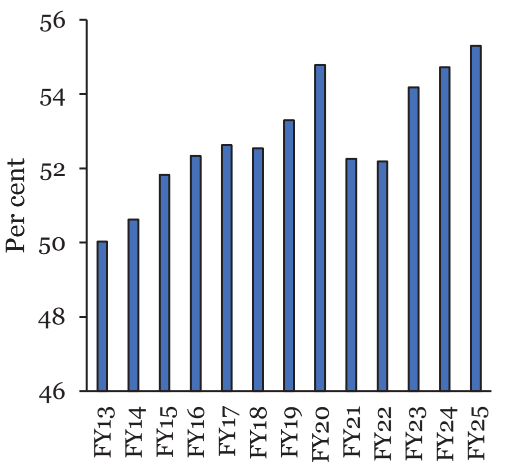

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।

8.5 पिछले दशक में, सेवाओं द्वारा वास्तविक जीवीए में साल-दर-साल होने वाले बदलाव के आधार पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि पिछले दशक में प्रत्येक वर्ष में छह प्रतिशत से अधिक रही है, सिवाय कोविड-19 महामारी के, जिसने वित्त वर्ष 2021 को प्रभावित किया। कोविड महामारी से पूर्व के वर्ष में सेवाओं की औसत वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी। महामारी के बाद, अर्थात वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं की औसत वृद्धि दर बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है।

8.6 सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: (i) व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, (ii) परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, (iii) वित्तीय सेवाएं, (iv) अचल संपत्ति, आवास और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व, (v) लोक प्रशासन और (vi) अन्य सेवाएं।

8.7 सेवा क्षेत्र में, लोक प्रशासन सेवाओं से वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल सेवाओं के जीवीए में 11-12 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल हुई है। सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में पिछले दशक (वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023) के दौरान सेवाओं के बीच सबसे अधिक उछाल था, जो पिछले दशक के दौरान 12.8 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से बढ़ी और वित्त वर्ष 2013 में समग्र जीवीए में

4 पंत, एस., और चक्रवर्ती, डी (2024)। क्या यह सेवा अभिविन्यास निम्न-मध्यम आय वाले देशों से विनिर्माण निर्यात को लाभ पहुंचा रहा है? डब्ल्यूबीईएस डेटा से फर्म-स्तरीय अनुभवजन्य साक्ष्य [वर्किंग पेपर]। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

इसकी हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 10.9 प्रतिशत हो गई। इस सेवा से महामारी के दौरान और उसके बाद, दोनों में ही उत्कृष्ट समुत्थानशीलता प्रदर्शित हुई है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) - सेवाएं

8.8 एचएसबीसी के इंडिया सर्विसेज पीएमआई से पता चलता है कि अगस्त 2021 से लगातार 41 महीनों तक सेवा क्षेत्र विस्तार क्षेत्र में रहा है। वित्त वर्ष 2025 के पहले पाँच महीनों में सूचकांक 60 अंक से ऊपर रहा। हालाँकि, सितंबर में सूचकांक दस महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया था, लेकिन अक्तूबर में यह जल्दी[5] ही वापस आ गया। हाल के डेटा से पता चलता है कि माँग में वृद्धि से नए व्यावसायिक अंतर्वाह को बढ़ावा मिलना जारी रहा, जिससे बदले में उत्पादन वृद्धि को सहायता मिली और फर्मों को अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर रखे जाने को प्रेरित किया। वित्त और बीमा से उप-क्षेत्र स्तर पर नए ऑर्डर और व्यावसायिक गतिविधि दोनों में सबसे मजबूत वृद्धि देखी गई।

चार्ट VIII.5: मजबूत बुनियादी सिद्धांत के समर्थन से वित्त वर्ष 2025 में पीएमआई सेवाएं मजबूत रहेंगी

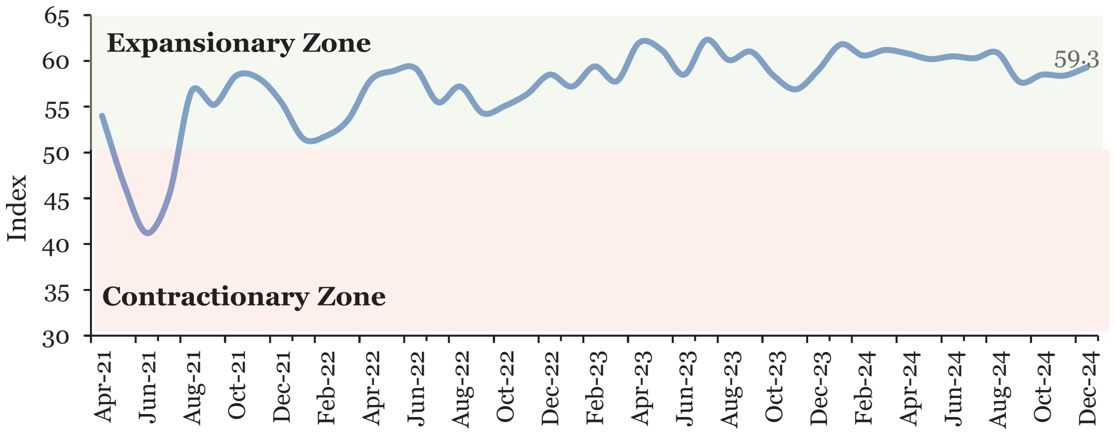

स्रोत: विभिन्न मासिक एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई रिपोर्टों से संकलित

नोट: सूचकांक 0 से 100 के बीच बदलता रहता है, 50 से ऊपर का स्तर पिछले माह की तुलना में समग्र वृद्धि को दर्शाता है, तथा 50 से नीचे का स्तर समग्र कमी को दर्शाता है।

सेवाओं संबंधी व्यापार

8.9 वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान स्थिर मूल्यों पर सेवाओं का निर्यात 11 प्रतिशत की दर से बढ़ा। भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर)[6] में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष पांच प्रमुख देशों में शामिल रहा। वित्त वर्ष 2024 में 5.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025 में भारत की सेवाओं के निर्यात में वृद्धि बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर में सेवाओं के आयात में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में इसी अवधि के दौरान 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

5 दिसंबर 2024 के लिए एचएसबीसी पीएमआई सेवा रिपोर्ट

6 डब्ल्यूटीओ के आँकड़े

चार्ट VIII.6: सेवाओं के जीवीए के प्रतिशत के रूप में सेवाओं का निर्यात (लोक प्रशासन का निवल)

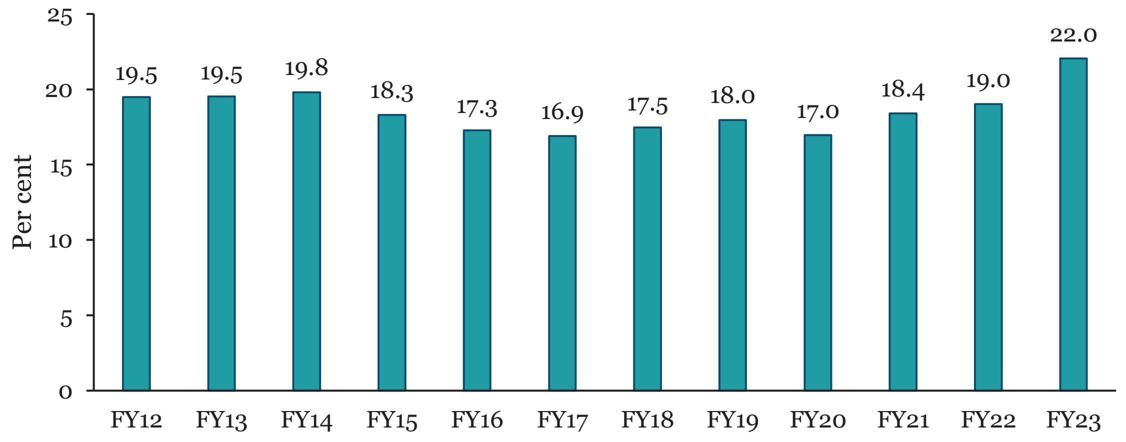

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

वित्तपोषण के स्रोत: बैंक ऋण और एफडीआई

8.10 नवंबर 2024 तक सेवा क्षेत्र को कुल बकाया बैंक ऋण[7] 48.5 लाख करोड़ रुपये है। सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेशेवर सेवाओं में सालाना आधार पर सबसे अधिक ऋण वृद्धि क्रमश: 22.5 और 19.4 प्रतिशत दर्ज की गई।

चार्ट VIII. 7: सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह

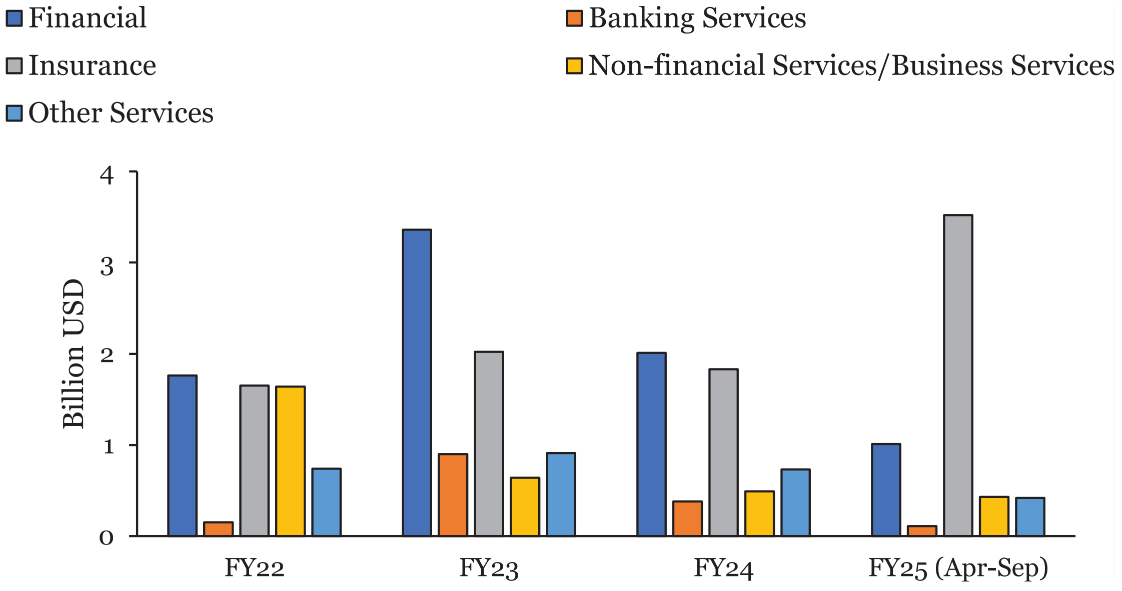

स्रोत: डीपीआईआईटी, वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं

7 आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रीय बैंक ऋण – नवंबर 2024, https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=59430

8.11 वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) में, एफडीआई[8] इक्विटी अंतर्वाह 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि सेवा क्षेत्र में इसी अवधि में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ। वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर)[9] में बीमा सेवाओं को सबसे अधिक 62 प्रतिशत से अधिक एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ, इसके बाद वित्तीय क्षेत्र का स्थान रहा, जिसने सेवा क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 18 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया।

बॉक्सः VIII.1: सेवाओं के लिए कार्यनीति - बहुआयामी विश्लेषण

नीति आयोग के वर्किंग पेपर ''संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचानः जीवीए, निर्यात और रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि'' में भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में सेवाओं की क्षमता का अध्ययन विभिन्न आयामों जैसे आउटपुट/मूल्य वर्धन, रोजगार और निर्यात में योगदान से किया गया है। इन प्रमुख आयामों पर विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों के प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर, सेवाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी नीतिगत सिफारिशें हैंः बचाव, तेजी लाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त।

चार्ट VIII.8: जीवीए, निर्यात और रोजगार के संदर्भ में सेवा क्षेत्र की क्षेत्रीय हिस्सेदारी

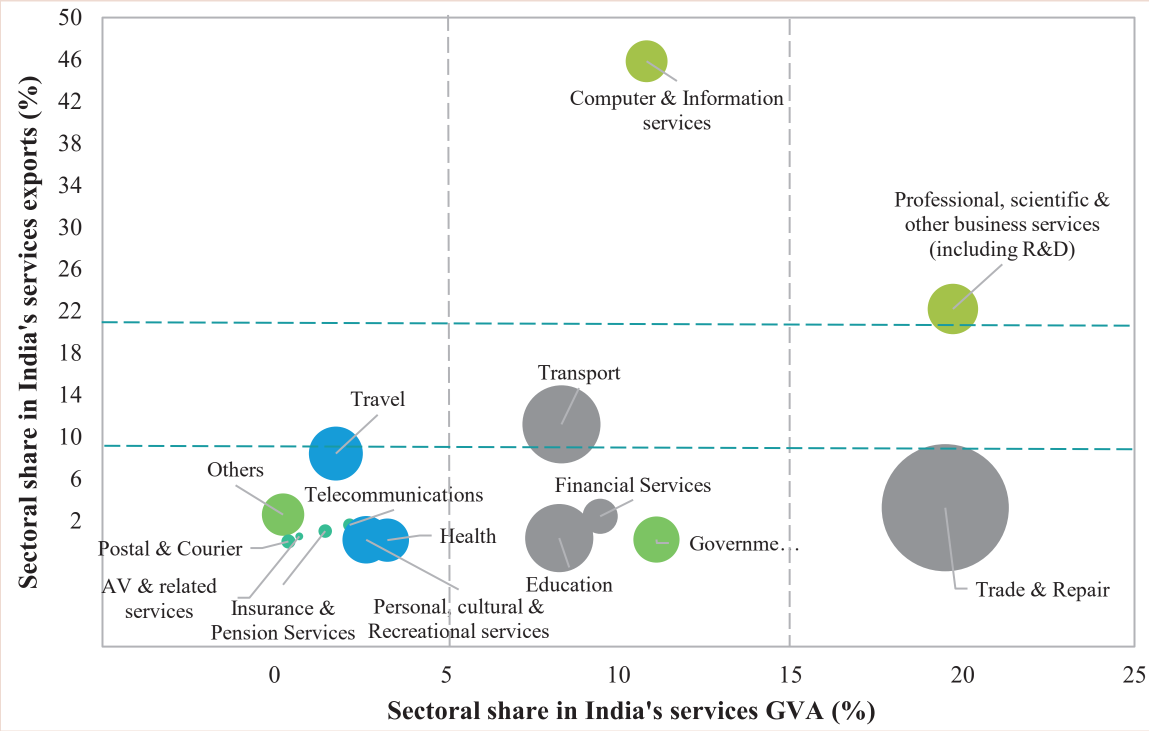

नोटः बुलबुले का आकार भारत के सेवा क्षेत्र के रोजगार में क्षेत्रीय हिस्सेदारी को दर्शाता है। निर्माण सेवाओं को सेवा निर्यात से बाहर रखा गया है, जबकि रियल एस्टेट सेवाओं (रोजगार और जीवीए) को 'अन्य व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीवीए और रोजगार आयामों के भीतर इसे मैप करने में चुनौतियों के कारण निर्माण क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है।
आरबीआई (निर्यात), पीएलएफएस (रोजगार) और एमओएसपीआई (जीवीए) के आंकड़ों पर आधारित

- बचाव हेतु क्षेत्र
- जिन क्षेत्रों में तेजी लाने की जरूरत है
- परिवर्तन हेतु क्षेत्र
- अप्रयुक्त क्षेत्र
- अन्य क्षेत्र

8 एफडीआई प्रवाह पर तिमाही तथ्य पत्रक, https://dpiit.gov.in/sites/default/files/FDI%20Factsheet%20September%202024.pdf
9 सेवा क्षेत्र में उप-क्षेत्रवार एफडीआई इक्विटी प्रवाह, डीपीआईआईटी, वित्त वर्ष 25 के आंकड़े अनंतिम हैं

बचाव हेतु क्षेत्र

उच्च निर्यात और जीवीए, कम रोजगार हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	कंप्यूटर एवं सूचना सेवाएँ, पेशेवर, वैज्ञानिक एवं अन्य व्यापारिक सेवाएँ

जिन क्षेत्रों में तेजी लाने की जरूरत है

निम्न-मध्यम निर्यात, मध्यम-उच्च जीवीए और रोजगार हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	व्यापार एवं मरम्मत, परिवहन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएँ

परिवर्तन हेतु क्षेत्र

कम निर्यात, जीवीए और रोजगार हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	यात्रा, स्वास्थ्य, वैयक्तिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सेवाएँ

अप्रयुक्त क्षेत्र

नगण्य निर्यात, जीवीए और रोजगार हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	दूरसंचार, बीमा एवं पेंशन सेवाएं, एवी और इससे संबंधित सेवाएं, डाक और कूरियर

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कार्यनीतिक सिफारिशों का सारांश नीचे प्रस्तुत है:

चार्ट VIII.9: कार्यनीतिक सिफारिशों का सारांश

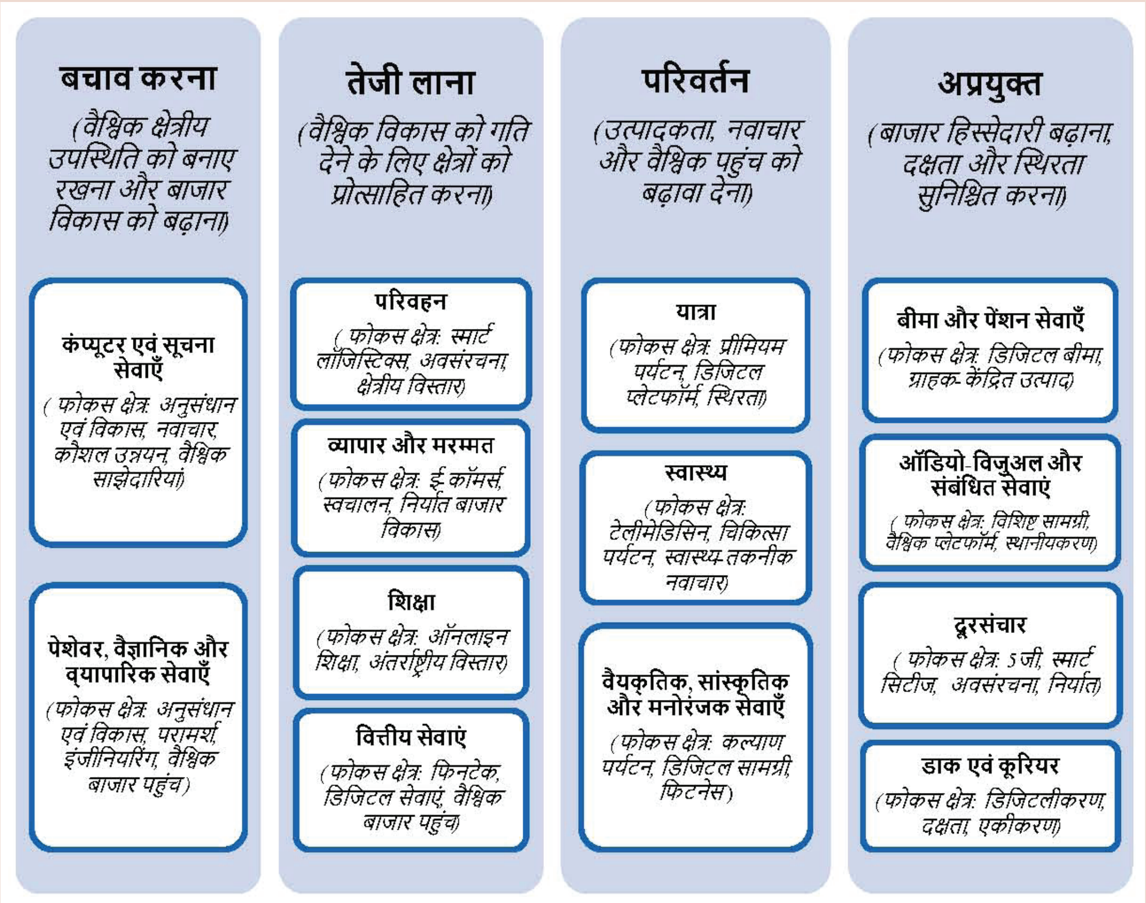

स्रोत: पंत. एस, शर्मा. पी, गुप्ता. ए और अग्रवाल पी. (2024, दिसंबर)। संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान: जीवीए, निर्यात और रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि। [वर्किंग पेपर] नीति आयोग. https://tinyurl.com/vxbbs5vj

लॉजिस्टिक्स और फिजिकल क्नेक्टिविटी-आधारित सेवाओं में प्रगति

भारतीय रेलवे: विकास को पटरी पर लाना

8.12 भारतीय रेलवे (आईआर) विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे से उत्पन्न पैसेंजर ट्रैफिक में पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में राजस्व अर्जित करने वाली माल ढुलाई में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट VIII.10: रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक में प्रगति

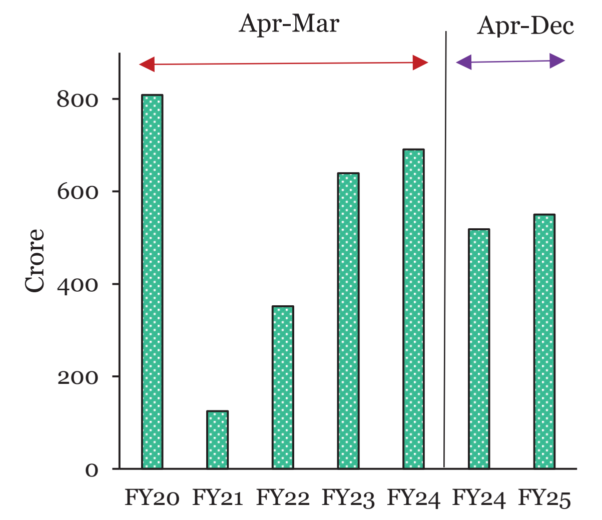

चार्ट VIII.11: रेलवे माल यातायात में प्रगति

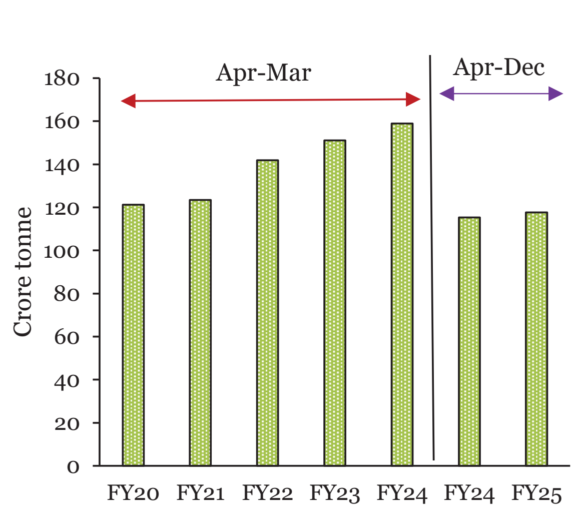

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.13 बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए, सरकार यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। नवंबर 2024 तक देश भर के कुल 7,325 रेलवे स्टेशनों में से 1351 स्टेशनों पर ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, 866 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस सिस्टम, 5605 स्टेशनों पर डिजिटल घड़ियाँ और 6071 स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तक 6112 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 2023 में मोबाइल कैटरिंग सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक नई नीति की शुरुआत की गई। अब तक 468 जोड़ी ट्रेनों में खानपान के लिए 557 बेस किचन चालू किए जा चुके हैं।

8.14 भारतीय रेल में डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ते कदम के परिणामस्वरूप, अक्तूबर 2024 तक आरक्षित क्षेत्र में ई-टिकटिंग का प्रतिशत 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में अनारक्षित क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से टिकटिंग 28 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर 2024 में लगभग 33 प्रतिशत हो गई है। भारतीय रेलवे ने लगभग 98 प्रतिशत मामलों में उपयुक्त मामलों में 24 घंटे के भीतर रिफंड सक्षम करने के लिए रिफंड प्रक्रिया को भी बदल दिया है। सभी काउंटरों पर डायनामिक क्यूआर कोड-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है। क्लाउड-नेटिव तकनीकों का उपयोग करके यात्री आरक्षण प्रणाली का पुनर्विकास किया जा रहा है। नए एप्लिकेशन में उच्च मापनीयता, उच्च प्रदर्शन, उच्च उपलब्धता, उच्च स्तर की सुरक्षा, प्रचालन में सुगमता और उच्च क्रियाशीलता जैसी विशेषताएं होंगी।

8.15 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत गौरव ट्रेनों को थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के रूप में पेश किया गया है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करती हैं। इस योजना के तहत, सेवा प्रदाता को भोजन, आवास, परिवहन, दर्शनीय स्थल, टूर गाइड आदि सहित व्यापक टूर सेवाएं प्रदान करनी हैं। अब तक, भारत गौरव ट्रेनों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 1,91,033 पर्यटकों को ले जाने के लिए कुल 325 यात्राएं संचालित की हैं।

सड़क परिवहन

8.16 परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन सबसे अधिक जीवीए उत्पन्न करता है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, परिवहन सेवाओं के कुल जीवीए में सड़क परिवहन का हिस्सा 78 प्रतिशत था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ाना सड़क परिवहन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, सरकार फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को अपनाकर टोल लगाने के पारंपरिक तरीकों से डिजिटल टोल लगाने की ओर अग्रसर हुई है। इससे टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय 734 सेकंड से घटकर 47 सेकंड[10] हो गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक सभी फोर लेन प्लस राष्ट्रीय राजमार्गों और हाई-स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोल लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर प्रत्येक 40-60 किलोमीटर पर एक हजार से अधिक वेसाइड सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई है।

8.17 सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार अभय परियोजना के साथ ट्रक चालक स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा चालकों के लिए नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य जांच प्रदान करने जैसी पहलों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की दिशा में भी काम कर रही है।

विमानन: ऊंची उड़ान

8.18 भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। हवाई यातायात में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, भारतीय एयरलाइनों ने वैश्विक स्तर पर विमानों के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए हैं।

10 https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AS302-pdf\source=pqals

चार्ट VIII.12: एयरवेज यात्री यातायात में प्रगति

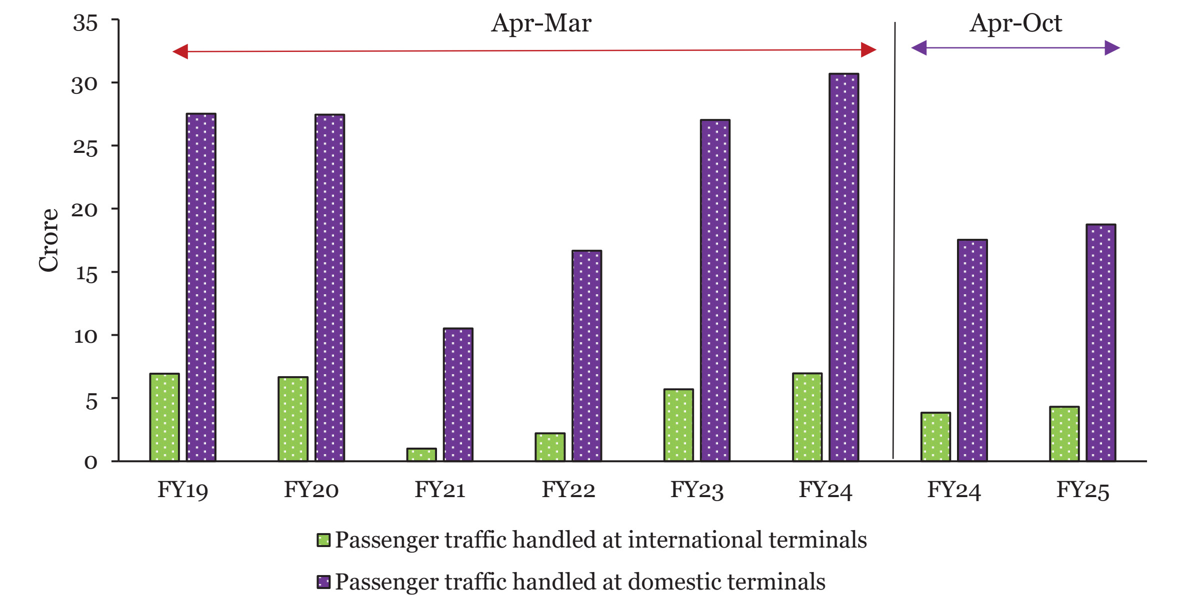

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

8.19 रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग के क्षेत्र में, सरकार मूल उपकरण विनिर्माताओं को भारत में सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इस क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नीतियां शुरू की हैं।

बॉक्स VIII.2: नए खंड – ड्रोन, लीजिंग और एमआरओ

- 31 अक्टूबर, 2024 तक भारत में ड्रोन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 140 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन, 18,862 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र जारी किए गए, 26,659 पंजीकृत ड्रोन और 82 स्वीकृत ड्रोन मॉडल (डीजीसीए टाईप प्रमाण-पत्र) शामिल हैं। ड्रोन विनिर्माण को समर्थन देने के लिए पीएलआई योजना के तहत लगभग 60.6 करोड़ वितरित किए गए हैं।
- 30 नवंबर, 2024 तक, 32 विमान पट्टे देने वाली संस्थाएं (अनंतिम सहित) जीआईएफटी-आईएफएससी में पंजीकृत हो चुकी हैं, तथा 53 विमानों और 52 इंजनों सहित 105 विमानन आस्तियों को पट्टे पर दे रही हैं।
- 12 जुलाई 2024 को सरकार ने आयातित विमान भागों और उपकरणों पर एक समान 5 प्रतिशत एकीकृत माल एवं सेवा कर की घोषणा की, जो एचएसएन वर्गीकरण के होते हुए भी लागू होगा।

8.20 पीएम गति शक्ति पहल का उद्देश्य पूरे देश में एक निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है। इस पहल के तहत, विमानन क्षेत्र को रेलवे, सड़क और जलमार्ग जैसे परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

चार्ट VIII.13: एयरवेज कार्गो ट्रैफिक में प्रगति - अंतरराष्ट्रीय

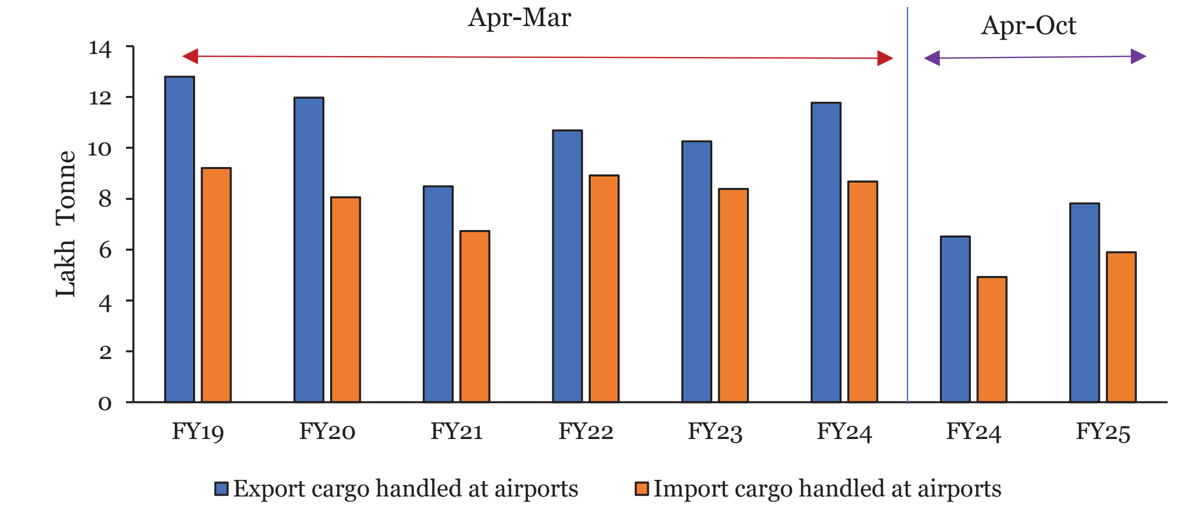

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पत्तन, जलमार्ग और पोत परिवहन: अवसरों की अधिकता

8.21 भारत के प्रमुख पत्तन बढ़ती व्यापार मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में कार्गो की आवाजाही 81.9 करोड़ मीट्रिक टन थी। वित्त वर्ष 2025 में, 87 करोड़ मीट्रिक टन के वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप, दिसंबर 2024 तक लगभग 62.2 करोड़ मीट्रिक टन माल की ढुलाई की जा चुकी है।

चार्ट VIII.14: पत्तन यातायात में प्रगति : प्रमुख पत्तनों पर संभाला गया माल

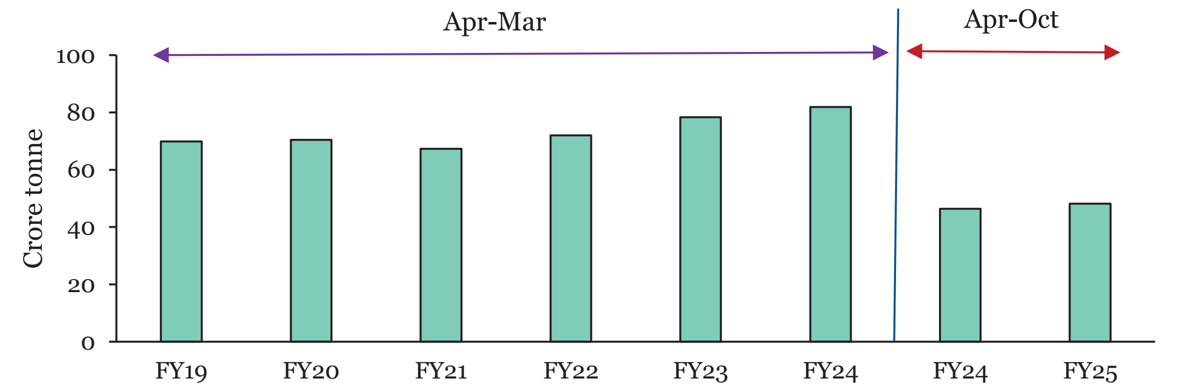

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

8.22 भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांचवे स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन वर्ष 2047 का शुभारंभ किया है।

8.23 अंतर्देशीय जल परिवहन में माल और यात्रियों के परिवहन के साधन के रूप में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। भारत में नदियों, नहरों और अन्य जलमार्गों का एक बड़ा भंडार है। भारत में जलमार्गों

की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850 किमी है। अक्तूबर 2024 तक, देश में 4,800 कि.मी. से अधिक के 26 जलमार्ग चालू हैं। सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय जलमार्गों पर यात्रियों की आवाजाही 3.36 करोड़ से अधिक थी, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में लगभग 67 लाख यात्रियों से अधिक थी।

चार्ट VIII.15: विभिन्न राज्यों में परिचालन जलमार्गों की नौगम्य लंबाई (कि.मी.)

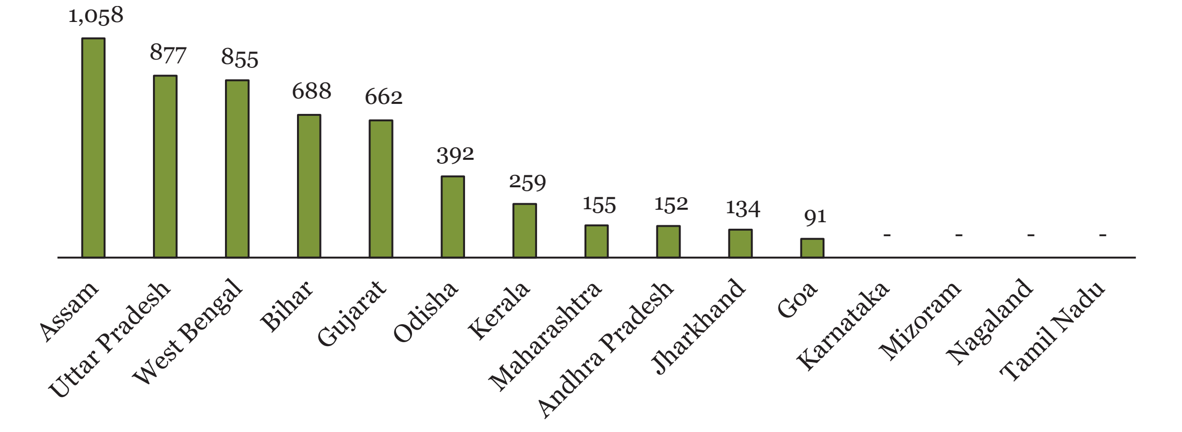

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अन्य सेवाएँ

पर्यटन और आतिथ्य

8.24 वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी से पहले के स्तर 5 प्रतिशत पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में 7.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई।

8.25 भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) 2023 में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 में विश्व आईटीए में भारत के आईटीए का 1.45 प्रतिशत हिस्सा है। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8 प्रतिशत प्राप्त हुआ और वर्ष 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14 वें स्थान पर पहुंच गया।

चार्ट VIII.16: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन और पर्यटन के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय चार्ट	VIII.17: घरेलू पर्यटकों की संख्या महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है
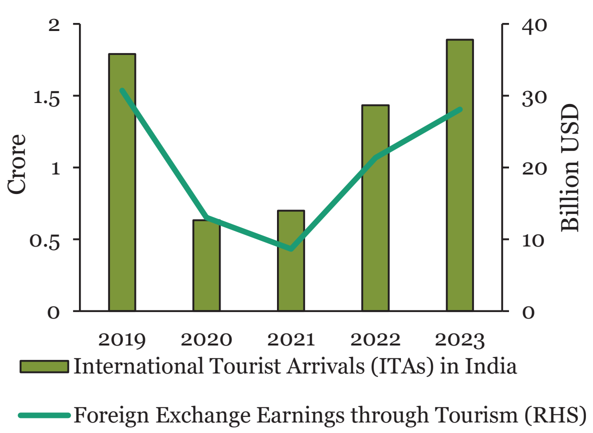	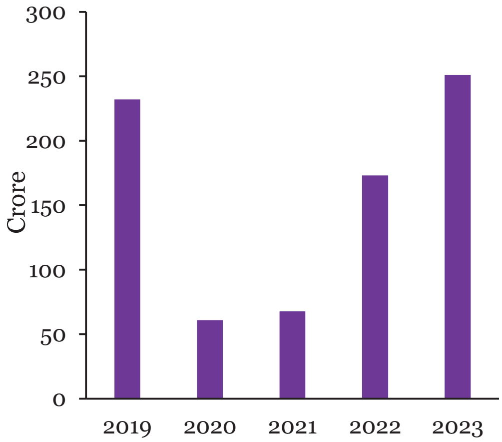
स्रोत: पर्यटन मंत्रालय	

रियल एस्टेट: अर्थव्यवस्था का निर्माण

8.26 भारत के रियल एस्टेट बाजार में आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक बाजार परिस्थितियों के कारण कार्यालय की मांग के साथ-साथ आवासीय बिक्री में भी मजबूत प्रदर्शन देखा गया। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अधिनियमन के बाद, भारत वर्ष 2024[11] में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 89 देशों में से 31वें स्थान पर रहा। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, सड़क नेटवर्क में वृद्धि और कनेक्टिविटी में सुधार के कारण रियल एस्टेट की मांग न केवल टियर 1 और टियर 2 शहरों में बल्कि पूरे देश में उभर रही है। भारत में आवास की मांग वर्ष 2036[12] तक 93 मिलियन यूनिट तक पहुँचने की संभावना है। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) का उदय वाणिज्यिक क्षेत्र के सकारात्मक मार्ग को और बढ़ाता है। आवासीय रियल एस्टेट बाजार ने वर्ष 2024 के पहले छह महीनों में बिक्री की मात्रा में 11 साल के उच्च स्तर को छुआ। इस अवधि के दौरान, शीर्ष आठ शहरों में कुल बिक्री में 11 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।[13]

11 https://www.jll.co.in/en/trends-and-insights/research/global-real-estate-transparency-index

12 कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

13 मासिक उद्योग अद्यतन रिपोर्ट, होटल और आतिथ्य अवलोकन, एचवीएस एनारॉक

चार्ट VIII.18: बकाया ऋण: आवासन और वाणिज्यिक रियल एस्टेट

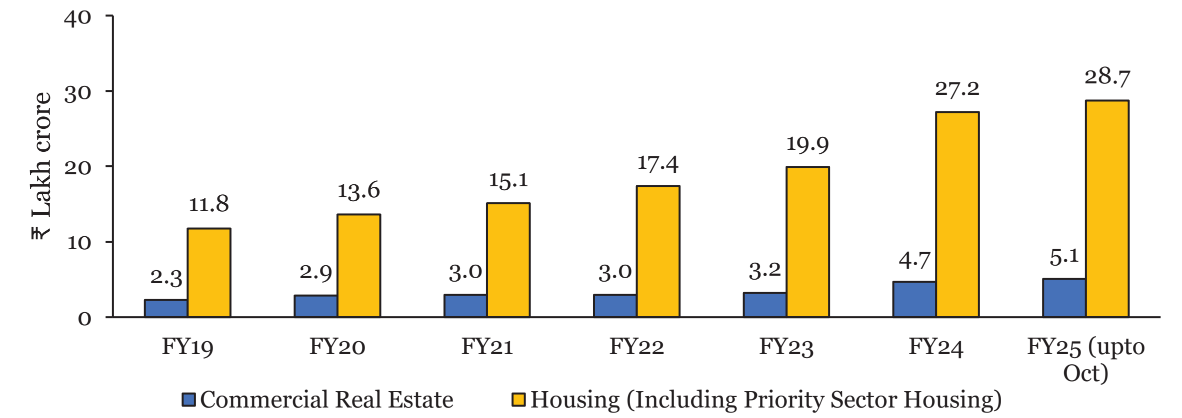

स्रोत: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का परिनियोजन, भारतीय रिजर्व बैंक

8.27 भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें अन्य लाभों के अलावा धोखाधड़ी से सुरक्षा, संवर्धित पारदर्शिता, समय पर परियोजना का वितरण और धन के दुरुपयोग को रोकने के उपाय शामिल हैं। जीएसटी ने राज्यों में एक एकीकृत कर प्रणाली लागू करके रियल एस्टेट लेनदेन में कराधान संरचना को सरल बनाने में मदद की है। इसने उचित चालान और दस्तावेजीकरण को प्रोत्साहित किया है, जिससे कर अपवंचन की गुंजाइश कम हो गई है। सरकार ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश साधन के रूप में आरईआईटी की शुरुआत की, जिससे निवेशकों को धन जमा करने और आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट में निवेश करने की अनुमति मिली। इससे वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार में नकदी बढ़ाने और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है। भवन योजनाओं को प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन से देरी में कमी आई है और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम का उद्देश्य एक व्यापक, सुलभ और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली सृजित करना है।

व्यापार सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएँ

8.28 भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग की वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति है और निर्यात बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नैसकॉम कार्यनीतिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत के तकनीकी उद्योग[14] ने व्यापक आर्थिक दबावों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच वित्त वर्ष 2024 में असाधारण समुत्थानशीलता दिखाई। उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 3.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (ई-कॉमर्स को छोड़कर) के साथ 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित करने का अनुमान लगाया है। तकनीकी निर्यात लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 3.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि घरेलू बाजार में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 24 में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। इस क्षेत्र ने अपनी स्थिति एक निवल नियुक्तिकर्ता

14 प्रौद्योगिकी उद्योग के राजस्व में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर उत्पाद और हार्डवेयर शामिल हैं।

के रूप में बनाए रखी, वित्त वर्ष 2024 में 60,000 कर्मचारियों को जोड़कर कार्यबल को 5.43 मिलियन तक पहुंचा दिया।

8.29 एंजल टैक्स (स्टार्टअप में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर) के उन्मूलन से देश की वैश्विक नवाचार और उद्यमशीलता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरक्षित बंदरगाह नियमों के दायरे का विस्तार करने और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से देश की हस्तांतरण मूल्य निर्धारण व्यवस्था को और अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाने, आईटी निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक क्षमता केंद्रों और आईटी सेवा उद्योग के लिए व्यापार को आसान बनाए जाने की उम्मीद है। अन्य सुधारों में 2 प्रतिशत समानीकरण शुल्क को समाप्त करना, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती में कमी, डेटा सेंटर निर्यात पर जीएसटी से राहत, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा एकत्र किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रह दर में कमी आदि शामिल हैं।

चार्ट VIII.19: सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रदर्शन: राजस्व और रोजगार सृजन

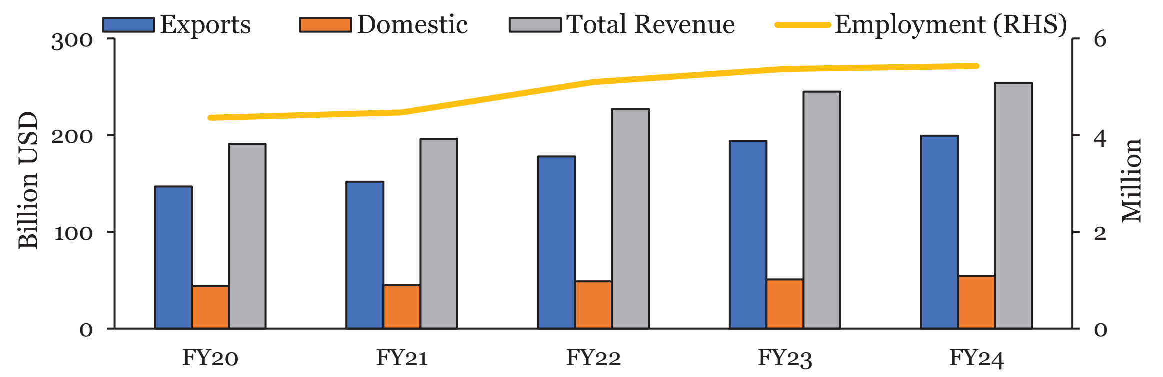

स्रोत: नैसकॉम
नोट: वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं

वैश्विक क्षमता केंद्र

8.30 भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य को नया आकार देने वाले कार्यनीतिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। भारत में जीसीसी की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1700 से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में जीसीसी में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं। पिछले पाँच वर्षों में, भारत वैश्विक जीसीसी विस्तार कार्यनीति में सबसे आगे रहा है, जिसमें 400 से अधिक नए जीसीसी और लगभग 1100 नई इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

8.31 जी.सी.सी. प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल रहे हैं। अग्रणी संगठन अपने तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को केंद्रीकृत कर रहे हैं। यह विशेष रूप से एयरोस्पेस, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट है, जहाँ कंपनियाँ अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने इंजीनियरिंग प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले पाँच वर्षों में, इंजीनियरिंग अनुसंधान

और विकास जी.सी.सी. की स्थापना दर समग्र जी.सी.सी. स्थापना की तुलना में 1.3 गुना अधिक तेजी से बढ़ी है, जो उच्च–मूल्य–वर्धित कार्य की ओर निरंतर बदलाव को उजागर करती है।

8.32 भारत ने अपने विशाल प्रतिभा पूल का लाभ उठाने में स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जो वैश्विक (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) स्टेम कार्यबल का 28 प्रतिशत और वैश्विक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिभा का 23 प्रतिशत है। पिछले एक दशक में, भारत में जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र काफी परिपक्व हो गया है, जो उत्पाद प्रबंधकों और आर्किटेक्ट्स जैसी उच्च–स्तरीय इंजीनियरिंग भूमिकाओं में आगे बढ़ रहा है, जिसमें 35 प्रतिशत परिवर्तन केंद्र आर्किटेक्ट्स[15] की मजबूत उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, जीसीसी के अंतर्गत वैश्विक भूमिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो वर्तमान में 6,500 से बढ़कर वर्ष 2030 तक 30,000 से अधिक होने की उम्मीद है, जिसे नेतृत्व विकसित करने के लिए मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन प्राप्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाना और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भारत की मजबूत मध्य–प्रबंधन प्रतिभा का दोहन करके जीसीसी परिदृश्य को और बढ़ाती है।

बॉक्स VIII.3: भारत में सेवा क्षेत्र में एआई को अपनाना

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई), स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, खुदरा और परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित सेवा क्षेत्र विभिन्न राष्ट्रीय पहलों और प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित, एआई को तेजी से अपनाने के लिए यह अग्रणी है।

वित्तः भारत में कई वित्तीय संस्थान और बैंक अपने संचालन को बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और अपनी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, एसबीआई द्वारा एसबीआई इंटेलिजेंट असिस्टेंट (एसआईए) चैटबॉट हैं जिनका उपयोग ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। बैंक धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन के लिए भी एआई का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए एमएल एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है।

दूरसंचार : एआई ग्राहक सहायता, नेटवर्क अनुकूलन और पूर्वानुमानित रखरखाव में सुधार करता है। भारत में कई दूरसंचार कंपनियाँ अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, संचालन को अनुकूलित करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई का लाभ उठा रही हैं। उदाहरण के लिए, एंड–टू–एंड टेलीकॉम नेटवर्क प्रबंधन के लिए एआई–संचालित प्लेटफॉर्म। नेटवर्क के हर पहलू को छूने वाले अत्याधुनिक बिग डेटा आर्किटेक्चर के शीर्ष पर निर्मित – कोर और रेडियो से लेकर टेलीकॉम सेवा प्रदाता के व्यावसायिक कार्यों तक का उपयोग किया जा रहा है। एमएल के माध्यम से स्मार्ट संचालन को सक्षम करने के लिए वाहकों के लिए तैयार किए गए क्लाउड–नेटिव डेटा लेक प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। वे असामान्य नेटवर्क पैटर्न का पता लगाने और इन पैटर्न के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने और अलर्ट करने के लिए एमएल का लाभ उठाते हैं ताकि नेटवर्क के लक्षण संचालन को प्रभावित करना शुरू करने से पहले सक्रिय मूल कारण विश्लेषण और समाधान हो सके।

खुदरा और ई–कॉमर्स : एआई व्यक्तिगत मार्केटिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। फैशन ई–कॉमर्स दिग्गज ग्राहकों को बेहतर और खोज–आधारित खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

15 नैसकॉम कार्यनीतिक समीक्षा रिपोर्ट 2024

परिवहन और लॉजिस्टिक्स : एआई एप्लीकेशन संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं और वितरण की सटीकता में सुधार करते हैं, जिससे कंपनियों को लागत कम करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में मदद मिलती है। पैकेजों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मार्ग नियोजन और अनुकूलन के लिए एआई का उपयोग किया जाता है। एआई-आधारित रोबोटिक सिस्टम का उपयोग उनके पूर्ति केंद्रों में छंटाई, पैकेजिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

दूरसंचार

8.33 स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता, डेटा की बढ़ती खपत और 5जी जैसी तकनीकों के आगमन के साथ भारत का दूरसंचार क्षेत्र विस्तार कर रहा है। 31 अक्तूबर, 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों, 84 प्रतिशत की कुल टेलीघनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड[16] उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा है। देश प्रति ग्राहक मोबाइल डेटा खपत में भी अग्रणी है और दुनिया की सबसे सस्ती डेटा दरें प्रदान करता है। विश्व भर में सबसे तेज 5जी रोलआउट की भारत की उपलब्धि दूरसंचार क्षेत्र में इसकी तकनीकी प्रगति को उजागर करती है।

चार्ट VIII.20: प्रति माह प्रति डेटा उपयोगकर्ता औसत वायरलेस डेटा उपयोग

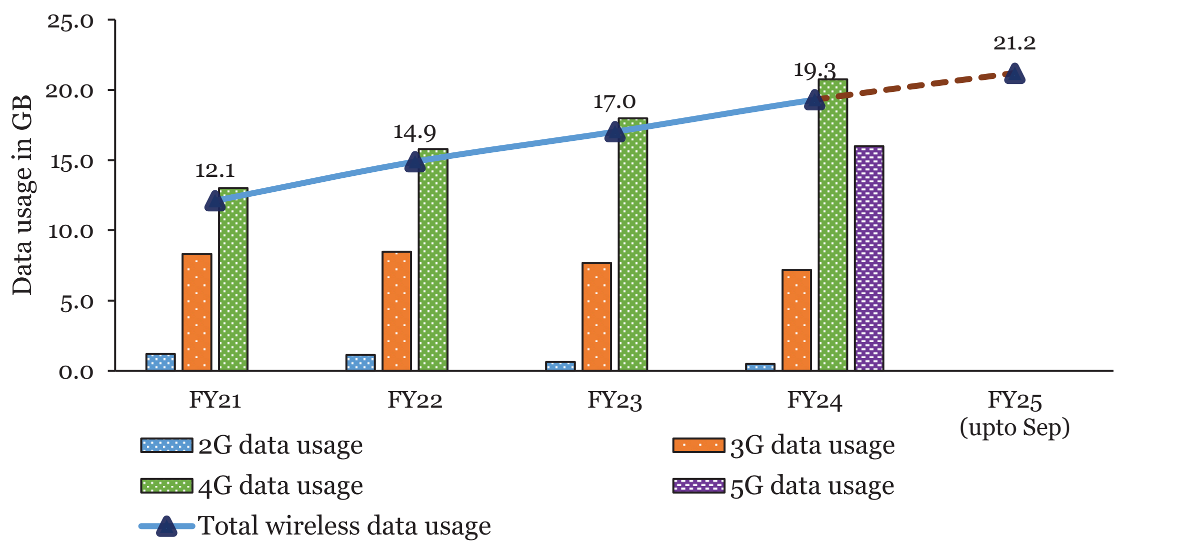

स्रोतः दूरसचांर विभाग

8.34 भारत के दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव आया है, जो प्रौद्योगिकी आयातक से प्रौद्योगिकी डेवलपर और निर्यातक के रूप में चल रहे प्रभावी परिवर्तन को दर्शाता है।

16 https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2024-12/PR_No.94of2024_0.pdf

बॉक्स VIII.4: सी-डॉट- भारत की दूरसंचार क्रांति का उत्प्रेरक

टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) स्वदेशी समाधानों के अनुसंधान एवं विकास तथा विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सी-डॉट ने लगातार अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का नेतृत्व किया है:

4जी और 5जी कोर नेटवर्क : सी-डॉट ने स्वदेशी 4जी और 5जी कोर समाधान विकसित करने, वैश्विक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करने और दूरसंचार आयात में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके नवाचार भारत की जरूरतों के अनुरूप सुरक्षित, स्केलेबल नेटवर्क की तैनाती का समर्थन करते हैं।

क्वांटम संचार प्रणाली : साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को स्वीकारते हुए, सी-डॉट ने क्वांटम एन्क्रिप्शन समाधान विकसित किया है, जो सरकार और कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है।

आपदा प्रबंधन समाधान : नागरिकों के लिए भू-लक्षित और स्वचालित बहु-जोखिम, मल्टीमीडिया पूर्व चेतावनी अलर्ट जैसी प्रौद्योगिकियों ने प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध भारत की तन्यकता को सुदृढ़ किया है।

साइबर सुरक्षा और समुत्थानशीलता : जैसे-जैसे दूरसंचार अवसंरचना विकसित होती है, वैसे-वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। सी-डॉट ने स्वदेशी साइबर सुरक्षा उपकरण विकसित किया है जो महत्वपूर्ण अवसंरचना की निगरानी और इसकी सुरक्षा करते हैं। ये उपकरण साइबर युद्ध से जुड़े जोखिमों को कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। सी-डॉट ने टेक्स्ट, छवि, ऑडियो और वीडियो फाइलों को साझा करने के लिए सुरक्षित कॉल और चैट प्रदान करने के लिए संवाद (SAMVAD) ऐप विकसित किया है और इसे कार्यनीतिक संगठनों में तैनात किया है।

घरेलू दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना : अपने सीसीआरपी (सी-डॉट सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम) के माध्यम से, सी-डॉट औद्योगिक जगत के लोगों के साथ साझेदारी करके स्वदेशी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देता है। यह पहल भारत के दूरसंचार अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है, जिसमें सी-डॉट कंपनियों को उन्नत तकनीक विकसित करने में मदद करने के लिए वित्तपोषण और विशेषज्ञता प्रदान करता है। सी-डॉट सीसीआरपी अवसंरचना के तहत इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप का भी समर्थन करता है। स्टार्टअप में नवाचारों और विचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (एनआईडीएचआई) और आविष्कार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

सी-डॉट की यात्रा भारत के एक दूरसंचार उपभोक्ता से प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक बनने की यात्रा का उदाहरण है, जो देश को डिजिटल संप्रभुता और समावेशी कनेक्टिविटी के भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

बॉक्स VIII.5: डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क: प्लेटफॉर्म से परे सोचना

महामारी ने व्यापार निरंतरता और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच प्रदान करने में डिजिटल कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। डिजिटल कॉमर्स अर्थव्यवस्था में समुत्थानशीलता लाने में भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर और भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल कॉमर्स के प्रचलित प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बड़े ई-कॉमर्स खिलाड़ी बाजार पर हावी हैं, जो स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और एमएसएमई जैसे छोटे विक्रेताओं की भागीदारी और समुत्थानशीलता को प्रभावित करता है। विक्रेताओं को अक्सर ग्राहक डेटा एक्सेस से लेकर उत्पाद दृश्यता तक के नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनका बाजार लाभ कम होता है और इन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ती है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक लोकतांत्रिक और अंतर-संचालन योग्य डिजिटल कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है, जिससे समावेशिता

और समानता को बढ़ावा मिलता है। ओएनडीसी खरीदारों और विक्रेताओं को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से लेन-देन करने में सक्षम बनाता है। यह ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम करने, व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने और व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों का विस्तार करके मदद करता है।

ओएनडीसी ने नवंबर 2024 के महीने में 1100 से अधिक शहरों में 14 मिलियन से ज्यादा लेन-देन दर्ज किए। भारत भर के 600 से अधिक शहरों और कस्बों में फैले ओएनडीसी नेटवर्क पर 7 लाख से ज्यादा विक्रेता और सेवा प्रदाता सक्रिय हैं। 190 से ज्यादा नेटवर्क प्रतिभागी नेटवर्क पर लाइव हैं। वर्तमान में, 7000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ने विभिन्न विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से ओएनडीसी नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए पंजीकरण कराया है। लगभग 400 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म उद्यमी और सामाजिक क्षेत्र के उद्यम नेटवर्क पर शामिल किए गए हैं। ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए मोबिलिटी 15 से ज्यादा शहरों में लाइव है, जिसमें लगभग 5.45 लाख टैक्सी और ऑटो चालक हैं।

नए आयाम स्थापित करना: पारंपरिक ई-कॉमर्स से आगे की सोच

सेवा के रूप में लॉजिस्टिक्स : ओएनडीसी 1200 से अधिक शहरों में एकीकृत प्रथम-मील, मध्य-मील और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के साथ निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए हाइपरलोकल और अंतर-शहर लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को एकीकृत कर रहा है।

वित्तीय सेवाएँ : ओएनडीसी की वित्तीय सेवा श्रेणी अगस्त 2024 में शुरू की गई थी। इसने 9 ऋण सेवा प्रदाता अनुप्रयोगों और 3 ऋणदाताओं के साथ एकीकरण किया, ताकि ऋण सेवाओं में पहुँच और दक्षता बढ़ाई जा सके। यह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए डेटा, डिजिलॉकर/ अपने ग्राहक को जानने के लिए आधार/पुनर्भुगतान के लिए ई-एनएसीएच / ई-मैनडेट और आधार ई- हस्ताक्षर के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को एकीकृत करता है। यह वित्तीय उत्पादों में कम लागत वाले वितरण और नवाचार की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत ऋण, स्वास्थ्य बीमा और म्यूचुअल फंड को सक्षम किया जा सकता है।

कवरेज का विस्तार: समावेशन को बढ़ाना

आज इस प्लैटफॉर्म पर 10 सक्रिय डोमेन, 110 नेटवर्क प्रतिभागी और करीब 6.5 लाख विक्रेता/सेवाप्रदाता हैं। इसके लॉन्च होने के बाद से ही इस प्लेटफॉर्म पर लेन-देन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खुदरा श्रेणी में, इस प्लेटफॉर्म पर 814 जिलों में 4.4 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर पूरे हुए हैं और 2.83 लाख विक्रेता इससे जुड़े हैं।[17]

ओएनडीसी ने भाषिनी-एआई-संचालित भाषा अनुवाद उपकरण के साथ मिलकर सारथी लॉन्च किया, जो व्यवसायों को उनके खरीदार-पक्ष ऐप बनाने में सहायता करने के लिए एक संदर्भ एप्लिकेशन है। अक्तूबर 2024 में[18], प्लेटफॉर्म ने कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में प्याज को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और ओटिपाई के साथ हाथ मिलाया।

17 https://opendata.ondc.org/

18 ओएनडीसी प्रेस विज्ञप्ति, 16 अक्तूबर, 2024 https://ondc.org/press-releases-details/?id=30

सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का राज्यवार विश्लेषण

8.35 इस समीक्षा के अध्याय 7 में औद्योगिक और सेवा सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए)[19] में राज्य-विशिष्ट पैटर्न प्रस्तुत करने के संदर्भ का उल्लेख किया गया है। वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत है। हालांकि, भारतीय राज्यों में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का वितरण एक स्पष्ट भौगोलिक संकेंद्रण के फैलाव को प्रकट करता है। वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में कर्नाटक और महाराष्ट्र का योगदान एक चौथाई से अधिक है। ये राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र के जीएसवीए का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा साझा करते हैं। इन राज्यों का कुल औद्योगिक जीएसवीए में भी 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जो दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे को सहायता करते हैं। दूसरी ओर 19 राज्यों का एक अन्य समूह सामूहिक रूप से सभी राज्यों के सेवा क्षेत्र के जीएसवीए के एक चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं (चार्ट VIII.21)।

चार्ट VIII .21: वित्त वर्ष 23 के लिए स्थिर मूल्यों पर सेवाओं में राज्यवार हिस्सेदारी

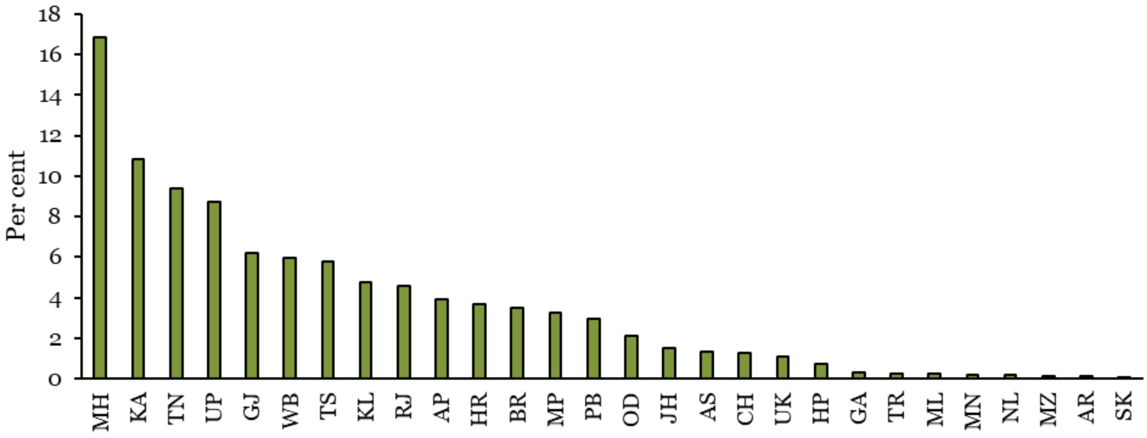

स्रोत: एमओएसपीआई द्वारा होस्ट किए गए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

नोट: इस खंड में प्रयुक्त राज्य कोड:

राज्य	कोड	राज्य	कोड	राज्य	कोड	राज्य	कोड
आंध्र प्रदेश	AP	हरियाणा	HR	मणिपुर	MN	सिक्किम	SK
अरुणाचल प्रदेश	AR	हिमाचल प्रदेश	HP	मेघालय	ML	तमिलनाडु	TN
असम	AS	झारखंड	JH	मिजोरम	MZ	तेलंगाना	TS
बिहार	BR	कर्नाटक	KA	नगालैंड	NL	त्रिपुरा	TR
छत्तीसगढ़	CH	केरल	KL	ओडिशा	OD	उत्तराखंड	UK
गोवा	GA	मध्य प्रदेश	MP	पंजाब	PB	उत्तर प्रदेश	UP
गुजरात	GJ	महाराष्ट्र	MH	राजस्थान	RJ	पश्चिम बंगाल	WB

8.36 विभिन्न सेवा गतिविधियों में, लोक प्रशासन एक विशिष्ट श्रेणी है जो राज्य में राज्य मशीनरी की शक्ति को दर्शाती है। यह राज्य की अपने राजस्व की ताकत, कर हस्तांतरण और राज्य के उधार सहित

19 इस अध्याय में, सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का तात्पर्य वित्त वर्ष 23 से है और इसे स्थिर (2011-12 की कीमतों) पर लिया गया है। ये जीएसवीए संख्याएँ संबंधित राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा अनुमानित की जाती हैं और एमओएसपीआई द्वारा होस्ट की जाती हैं। राज्य जीएसवीए का योग एमओएसपीआई द्वारा अनुमानित राष्ट्रीय जीवीए से भिन्न हो सकता है। राज्य की जनसंख्या, जहाँ भी उपयोग की जाती है, उनके जीएसडीपी गणना के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आँकड़ों को संदर्भित करती है।

केंद्रीय अंतरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक साथ राज्य की व्यय करने की क्षमता को परिभाषित करते हैं। यह अन्य सेवाओं से स्वतंत्र है जो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक रूप से संचालित हैं।

चार्ट VIII.22: कुल जीएसवीए में लोक प्रशासन का हिस्सा

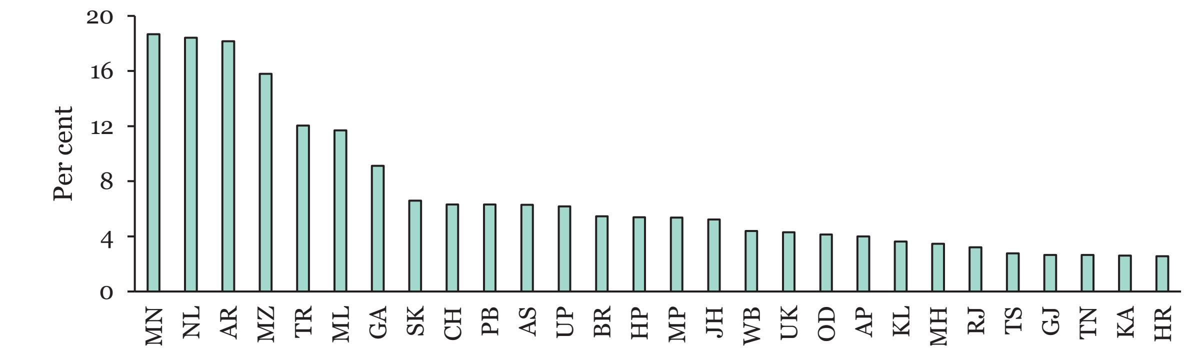

स्रोतः एमओएसपीआई द्वारा होस्ट किए गए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

8.37 कई पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं राज्य और केंद्र सरकारों के संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और वाणिज्यिक सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में प्राकृतिक नुकसान हैं। (चार्ट VIII. 22)

चार्ट VIII.23: कुल जीएसवीए में सेवाओं का हिस्सा और प्रति व्यक्ति जीएसवीए सेवाएं (लोक प्रशासन के निवल)

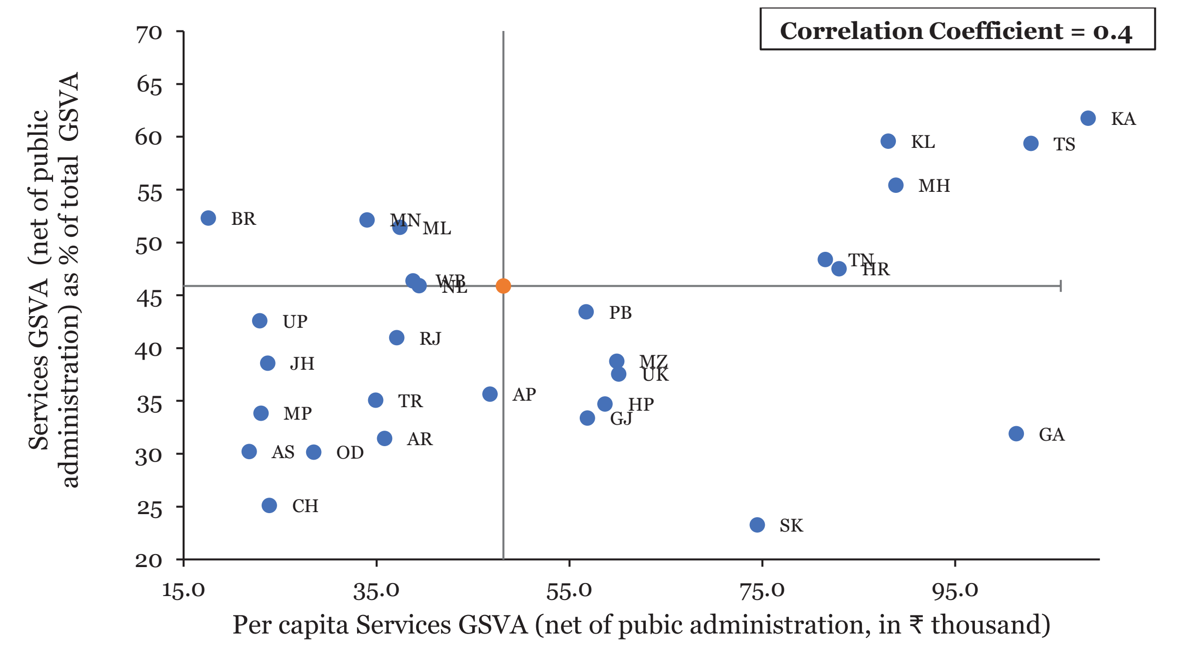

स्रोतः एमओएसपीआई द्वारा होस्ट किए गए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

8.38 कुल जीएसवीए (राज्य अर्थव्यवस्था की सेवा गहनता के रूप में परिभाषित) में सेवाओं की हिस्सेदारी और प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए के बीच संबंधों में चार अलग-अलग परिदृश्य हैं।

i. कम सेवा तीव्रता, कम प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए;

ii. कम सेवा तीव्रता, उच्च प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए;

iii. उच्च सेवा गहनता, कम प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए; तथा,

iv. उच्च सेवा गहनता, उच्च प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए।

8.39 उपरोक्त श्रेणी (ii) यह दर्शाती है कि वाणिज्यिक सेवाओं की उत्पादकता अधिक है। इसके विपरीत, श्रेणी (iii) उच्च स्तर की आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त उत्पादक होने के बिना वाणिज्यिक सेवा गतिविधियों पर उच्च निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है। पूरक जानकारी का विश्लेषण किए बिना अन्य दो श्रेणियों में आने वाले राज्यों से ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि, श्रेणी (iv) में, कुछ राज्य पैटर्न बहुत स्पष्ट हैं- कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना की स्थिति मुख्य रूप से आईटी सेवाओं की बड़ी उपस्थिति से स्पष्ट होती है, महाराष्ट्र की स्थिति मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों की अपनी ताकत के कारण है, और केरल की स्थिति मुख्य रूप से व्यापार, वित्तीय और अचल संपत्ति सेवाओं की मजबूत उपस्थिति के कारण है। निम्नलिखित तीन चार्ट सेवा गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं जो सार्वजनिक प्रशासन के कुल सेवा जीएसवीए के दो-तिहाई से अधिक की स्थापना करते हैं। ये तीन चार्ट, चार्ट VIII.23 में दर्शाए गए पैटर्न संबंधी कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।

चार्ट VIII.24: व्यापार और मरम्मत, होटल और रेस्तरां सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए

चार्ट VIII.25: वित्तीय सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए

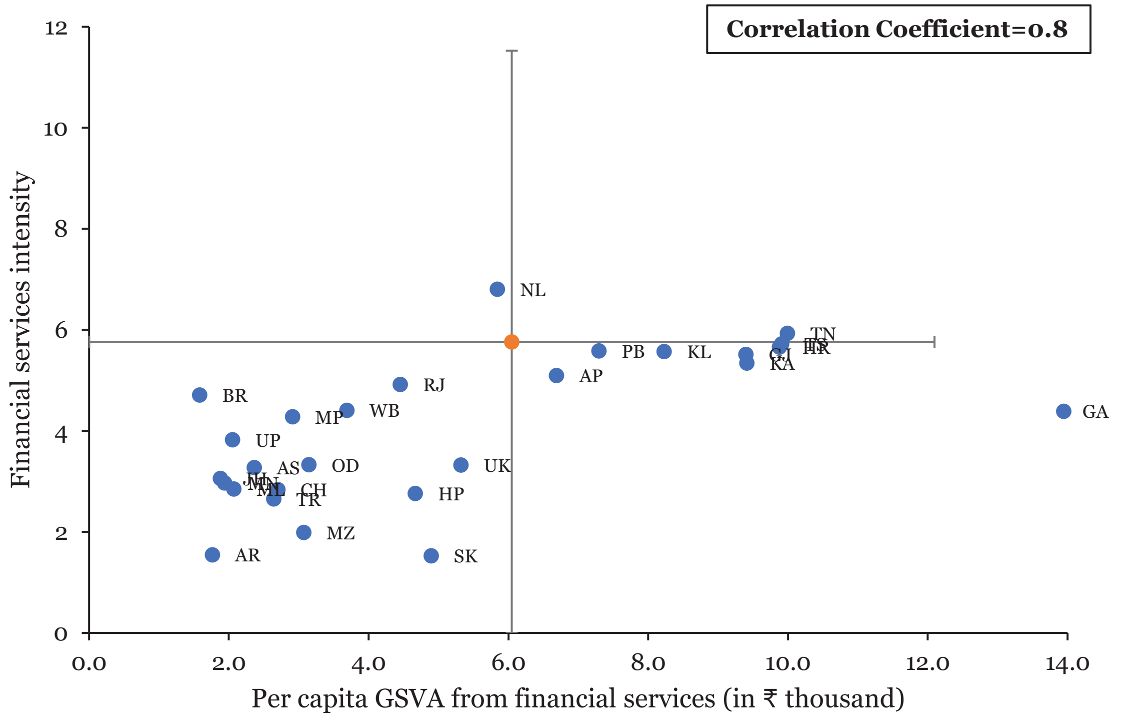

चार्ट VIII.26: रियल ऐस्टेट, आवास स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए

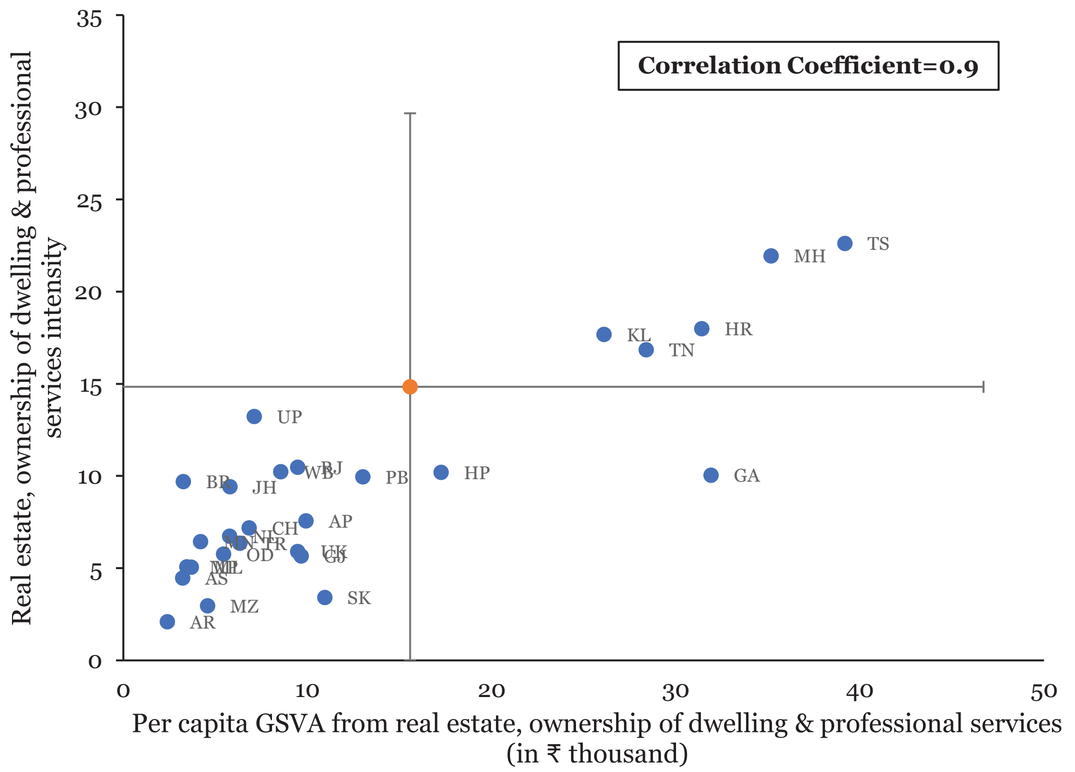

स्रोत: एमओएसपीआई द्वारा होस्ट किए गए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

8.40 मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम जैसे राज्यों में एक तिहाई से अधिक सेवाएँ जीएसवीए व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां से आती हैं, आंशिक रूप से पर्यटन के कारण। कई बड़े राज्यों में व्यापार और मरम्मत की गहनता मौजूद है जो राष्ट्रीय औसत के करीब या उससे अधिक है, इन राज्यों में कम मूल्य वर्धित व्यापार की बड़ी उपस्थिति को दर्शाती है। इनमें से कई राज्य अपेक्षाकृत कम औद्योगिकीकृत भी हैं। (अध्याय 7 देखें)।

8.41 वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं का कुछ राज्यों में बहुत उच्च स्तर का संकेन्द्रण है। सेवा क्षेत्र में वित्तीय सेवाएँ महाराष्ट्र (मुंबई), तमिलनाडु, गुजरात (गिफ्ट सिटी) और कर्नाटक में अत्यधिक संकेन्द्रित हैं, जो कुल वित्तीय सेवाओं के जीएसवीए का 50 प्रतिशत से अधिक है। (महाराष्ट्र को चार्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि यह एक बड़ा सकारात्मक अपवाद है)।

8.42 कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु में उनकी सेवाओं के जीएसवीए का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रियल एस्टेट, आवास के स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं से आता है। (कर्नाटक को चार्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि यह एक सकारात्मक अपवाद है) कर्नाटक (बेंगलुरु), तेलंगाना (हैदराबाद) और महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा (गुरुग्राम) और तमिलनाडु (चेन्नई) में आईटी और फिनटेक सेवाओं का संकेन्द्रण है, जिससे कार्यालय और आवासीय स्थान की उच्च मांग है।

चार्ट VIII.27: प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए और प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए (लोक प्रशासन का निवल)

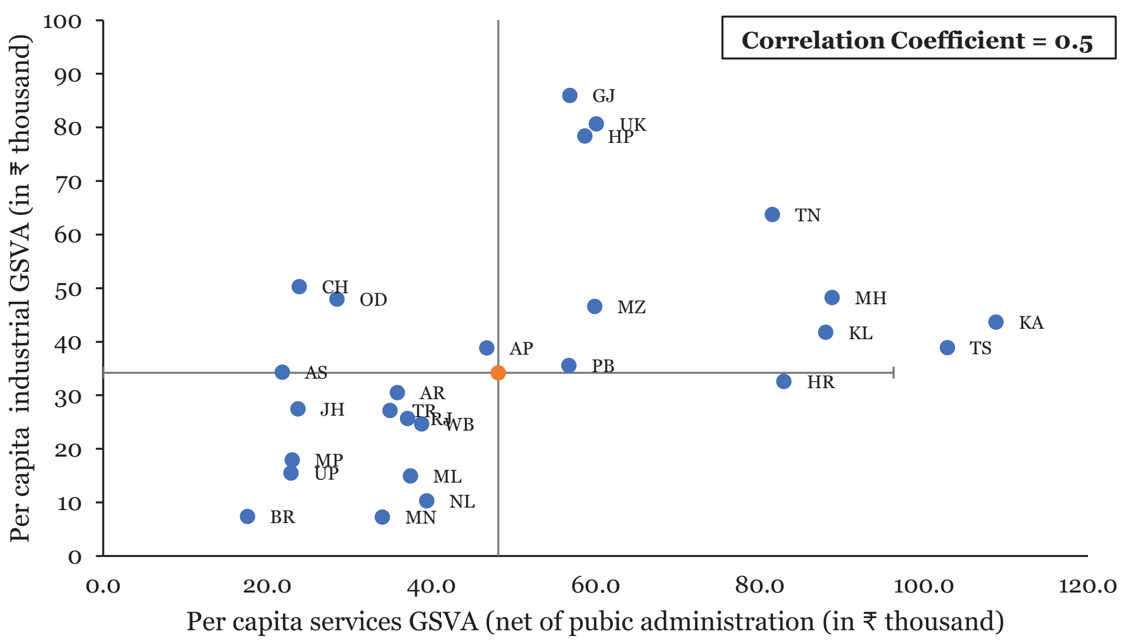

स्रोतः एमओएसपीआई द्वारा होस्ट किए गए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

8.43 चार्ट VIII.27 इस अध्याय और अध्याय 7 से प्राप्त राज्य पैटर्न को जोड़ता है। (सिक्किम और गोवा को यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि वे अपवाद हैं)। यह मुख्यतः विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक लाभों को दर्शाता है।

8.44 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, राज्यों को प्रति व्यक्ति जीएसवीए के संदर्भ में उनकी सेवा और औद्योगिक प्रदर्शन के आधार पर चार अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

i. प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक जीएसवीए वाले राज्य: ये गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा है, जबकि उनके पास सेवा क्षेत्र कम है। यह दर्शाता है कि इन राज्यों को अपने औद्योगीकरण और औद्योगिक उत्पादकता में तेजी लाने से काफी लाभ होगा जो उद्योगों के अधिक 'सेवाकरण' में चल रहे रुझानों के माध्यम से उनके सेवा क्षेत्रों को मजबूत करेगा।[20]

ii. सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन: कर्नाटक, तेलंगाना, और केरल जैसे राज्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए और जीएसवीए में सेवा हिस्सेदारी अत्यधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए औसत के आसपास है। यह क्षेत्र शहरीकृत सेवा-संचालित अर्थव्यवस्थाओं पर मुख्य रूप से निर्भर हैं।

iii. दोहरी ताकतें- औद्योगिक और सेवा: महाराष्ट्र और तमिलनाडु विशेष रूप से ऐसे राज्यों का प्रतिनित्व करते हैं जिनकी औद्योगिक और सेवा जीएसवीए काफी मजबूत हैं। उनकी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ विनिर्माण को व्यापार, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के साथ एकीकृत करती हैं।

iv. सुधार की संभावना वाले राज्य: जहाँ सामान्य तौर पर सभी राज्यों में व्यापार संबंधी सुधार अपेक्षित है, चौथी श्रेणी में विशिष्ट रूप से वे राज्य शामिल हैं जिनमें सुधार आधारित विकास की महत्वपूर्ण संभावना है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

8.45 डीपीआईआईटी की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी)[21] के अनुसार, जो राज्यों को व्यवसाय सुधार शुरू करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है, उद्योग द्वारा समर्थित सेवा गहनता वाले राज्य वे राज्य हैं जिन्होंने अपने समकक्ष राज्यों की तुलना में बड़ी संख्या में सुधार शुरू किए हैं और शीर्ष उपलब्धि और उपलब्धि की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार, राज्य में औद्योगिक और सेवा विकास के लिए व्यवसाय सुधार शुरू करना आवश्यक है।

8.46 असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, असंगठित क्षेत्र से संबंधित अनुमानित संस्थानों की संख्या 6.5 करोड़ है। इनमें से 72.6 प्रतिशत उद्यम सेवा क्षेत्र में प्रचालित है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में इन उद्यमों की पर्याप्तता है। ये उद्यम, हालांकि रोजगार एवं आय के मामले में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान दे रहे हैं, परंतु वे आम तौर पर निगमन द्वारा दिए जाने वाले लाभों जैसे कर लाभ और विश्वसनीयता को खो रहे हैं, जो उन्हें बेहतर ग्राहक संबंध बनाने, ऋण तक पहुंच और स्थायित्व प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जो उन्हें अपने व्यवसाय संचालन आदि को निरंतरता प्रदान करने में मदद करेगा। अनुपालन कठिनाइयों को कम करने वाली नीतिगत पहल के माध्यम से राज्य इन उद्यमों के निगमन में तेजी ला सकते हैं।

20 पंत, एस., और चक्रवर्ती, डी. (2024)। क्या इस सेवा अभिविन्यास निम्न-मध्यम आय वाले देशों से विनिर्माण निर्यात को लाभ पहुंचा रहा है? डब्ल्यूबीईएस डेटा से फर्म-स्तरीय अनुभवजन्य साक्ष्य [वर्किंग पेपर]। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

21 https://eodb.dpiit.gov.in/Home?year=wM54HFmV7pBOTrogIzA97w_eee__eee_

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

8.47 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में, हमने बताया कि दो महत्वपूर्ण परिवर्तनः घरेलू सेवा वितरण का तेजी से प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन और भारत के सेवा निर्यात का विविधीकरण, भारत के सेवा परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। इस परिवर्तन के शीर्ष पर वित्तीय और पेशेवर सेवाएँ हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में, भारत में कुल सेवा क्षेत्र जीवीए वृद्धि का लगभग 45 प्रतिशत वित्तीय, रियल एस्टेट, किराये और पेशेवर सेवाओं के कारण था; लगभग उतना ही जितना पिछले दशक के दौरान हुआ था। वैश्विक स्तर पर, सेवाएँ वर्तमान में उन देशों में भी वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ माल के व्यापार में उछाल के कारण विनिर्माण में मंदी है। इससे सेवा निर्यात और घरेलू सेवा उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

8.48 साथ ही, प्रमुख चुनावी परिणामों के बाद वैश्विक नीतियों में हाल ही में हुए बदलावों के मद्देनजर आईटी और पेशेवर सेवाओं के विकास में नए जोखिम सामने आए हैं। विनियामकों ने ऑडिट की गुणवत्ता पर अपतटीय कार्य के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। व्यक्त की गई सामान्य चिंताएँ पारंपरिक प्रशिक्षुता मॉडल के टूटने, अपर्याप्त प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, भाषा अवरोधों और जटिल मामलों में निर्देशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में असमर्थता, दूरस्थ लेखा परीक्षकों की सूचना अंतराल, गोपनीयता के खोने के जोखिम और शामिल देशों में विनियामक प्रावधानों में अंतर के कारण अनुपालन में कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। ये कथित जोखिम निर्यात-आधारित सेवाओं के विकास के लिए नकारात्मक जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

8.49 घरेलू स्तर पर, गैर-सेवा आर्थिक गतिविधियों की अंतर्निहित सेवा सामग्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा प्रमाणित है। विनिर्माण के 'सेवाकरण', अर्थात विनिर्माण उत्पादन और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्धन में सेवाओं के बढ़ते उपयोग को उजागर करने वाली जानकारी में भी वृद्धि हुई है।[22] इसका अर्थ है कि विनिर्माण में वृद्धि का सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही, विनिर्माण और वित्त, खुदरा और वाणिज्य, दूरसंचार, और परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स जैसी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती पहुंच अंतर्निहित सेवाओं की मांग की संरचना को बदल रही है।

8.50 उभरते हुए सेवा परिदृश्य की यह तस्वीर दो निष्कर्ष स्वतः ही उत्पन्न करती है। पहला, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है कि उपयुक्त डिजिटल और तकनीकी कौशल वाले जनशक्ति (और क्षेत्र) को एआई पहुंच से लाभ मिलता है। इसलिए, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की प्रगति के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक श्रम शक्ति के उचित कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है। बजट 2024-25 में की गई महत्वपूर्ण पहलों को सरकार, निजी क्षेत्र और कौशल संस्थानों के सभी स्तरों के तालमेलपूर्ण प्रयासों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, जमीनी स्तर पर जटिल प्रक्रियाओं, विनियमों और नियमों की समीक्षा और संशोधन की तत्काल आवश्यकता है जो विनिर्माण और सेवाओं दोनों में बाधा डालते हैं। अध्याय 5 इस संबंध में कई सुझाव देता है। ये संभावित लगातार वैश्विक बाधाओं के विरूध *समुत्थानशील* बनाने में मदद करेंगे।

******

22 पंत, एस., और चक्रवर्ती, डी. (2024)। क्या इस सेवा अभिविन्यास निम्न-मध्यम आय वाले देशों से विनिर्माण निर्यात को लाभ पहुंचा रहा है? डब्ल्यूबीईएस डेटा से फर्म-स्तरीय अनुभवजन्य साक्ष्य [वर्किंग पेपर]। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)